आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 01.06.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की परियोजनाओं का निरीक्षण किया।
- प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। शासन–प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।
- स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तेज की तैयारियां। निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं।
- हरिद्वार जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

झील संरक्षण

नैनीताल जिले में झीलों के संरक्षण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आवास व राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट– भीमताल झील के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़ 67 लाख रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके तहत झील के आसपास स्थित प्रमुख पार्कों का पुनर्विकास, दीनदयाल पार्क के समीप बोटिंग डॉक का विकास, झील किनारे कॉबल स्टोन पैदल मार्ग, उद्यानों का सौंदर्यीकरण और पार्किंग व्यवस्था में सुधार सहित अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी कार्यों को मानकों के अनुरूप शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नौकुचियाताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 21 करोड़ रूपये की योजना पर किए जा रहे कार्यों को भी निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने निर्देश दिए गए। सचिव ने भवाली में लकड़ी टाल क्षेत्र में मल्टीलेवल कार पार्किंग और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य, बेसमेंट में पार्किंग और भूतल तथा प्रथम तल पर लगभग 40 दुकानों के प्रस्तावित निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य कार्यों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

चारधाम यात्रा

प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। शासन–प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। खराब मौसम को देखते हुए धाम क्षेत्र और यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही हैं। वहीं, रूद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन रजवान ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए केदारनाथ पैदल मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। साथ ही जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 647 जवान तैनात हैं, जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सहायता में जुटे हुए हैं।

धारा–163

टिहरी जिले में धनोल्टी की उप जिलाधिकारी नीलू चावला ने जिले की सीमा अंतर्गत तीन सौ मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ ही अगले छह माह तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों और संगठनों के धरना–प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, मार्ग अवरोध और कार्यस्थल पर अनाधिकृत प्रवेश जैसी गतिविधियों की आशंका है। इसे देखते हुए शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत परियोजना के समस्त कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना–प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग और हथियार, ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर व निर्माण क्षेत्र में, अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों को अपने घरों में आने–जाने व कृषि कार्यों के लिए शांतिपूर्ण आवाजाही की अनुमति दी गई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि निगम की टीम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर के संवेदनशील कचरा स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कूड़ा उठाने वाले वाहनों की समय–समय पर निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गीले और सूखे कूड़े के अलग–अलग निस्तारण और सेग्रीगेशन को लेकर भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर सके।

अतिक्रमण

हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आगामी कांवड़ मेले और अर्द्धकुंभ से पहले जिलेभर में यह विशेष अभियान चलेगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले में विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि पर हुए अतिक्रमणों की सूची तैयार की जा रही है। कब्जाधारियों को पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम समाज, तालाब, नहर, नदी और अन्य सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। साथ ही जहां से कब्जा हटाया जाएगा, वहां दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही भी तय होगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बारहवीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है।